Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

NCCT CO-OP NEWS BULLETIN

DATE: 24.01.2024

Date: 24.01.2024

Sr No	Date	Publication	Edition	Page no.	Circulation
1.	24-01-2024	Free Press Gujarat	Ahmedabad	3	
2.	24-01-2024	Palash	Ahmedabad	4	
3.	24-01-2024	Western Times	Ahmedabad	2	
4.	24-01-2024	Rajasthan Patrika	Jaipur	17	
5.	24-01-2024	Dainik Jalte Deep	Jaipur	7	
6.	24-01-2024	Business Remedies	Jaipur	6	
7.	24-01-2024	Dainik Bhor	Jaipur	3	
8.	24-01-2024	Bureau Sandesh	Jaipur	2	
9.	24-01-2024	Dainik Taj Bharti	Jaipur	3	

Publication:	Free Press Gujarat	Edition: Ahmedabad	Print
Published Date:	January 24, 2024		

National Council for Co-operative Training to help 30000 PACS

Ahmedabad, The National Council for Co-operative Training (NCCT) will help 30,000 Primary Agriculture Credit Societies (PACS) in transforming them as Common Service Centres (CSCs) by imparting training to their employees. The training programme for employees of 30,000 PACS, which have enrolled themselves as Common Service Centres (CSCs), will be conducted during February and March. After the training programme, these PACS will become one-stop shops for many essential services like banking, insurance, Aadhaar updates, and all government-to-citizen e-services. National Council for Co-operative Training (NCCT) is an Autonomous Society promoted by Ministry of Cooperation, Government of India. Under the dynamic leadership of Union Home Minister and Union Cooperation Minister, the Ministry of Cooperation has taken several measures to strengthen PACS, which are grass root level arms of the short term cooperative credit structure. Common Service Centres (CSC) are the touchpoints for delivering government-to-citizen e-services directly to citizens without needing to visit government offices.

Publication:	Palash	Edition: Ahmedabad	Print
Published Date:	January 24, 2024		

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद 30000 पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन में मदद करेगी

22 जनवरी- राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) 30,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में बदलने में मदद करेगी।

30,000 पैक्स के कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम, फरवरी और मार्च के दौरान आयोजित किया जाएगा ये 30,000 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, ये पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/ अपडेट और सरकार और नागरिकों के बीच सभी आवश्यक सेवाओं सेवाएँ प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप शॉप बन जाएंगे।

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित एक स्वशासी सोसायटी है7

केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के कुशल नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की मूल स्तर हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सरकारी ऑफिसो में जाने की आवश्यकता के बिना नागरिकों को सीधे ई-सेवाएं प्रदान करते हैं।

साथ ही, वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों के साथ एक भौतिक बुनियादी ढांचा स्थापित करते हैं।

सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और अत्यावश्यक सेवाएं लोगों के करीब लाकर उनका बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एनसीसीटी के एक अधिकारी ने कहा कि 30,000 पैक्स को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी 2024 से शुरू होने वाला है, जो उन्हें सीएससी की विभिन्न सेवाओं की सभी जानकारी देने में सक्षम बनाएगा।

एनसीसीटी से जुड़े लगभग 80 मास्टर ट्रेनर पुरे देश के 570 जिलों में फैले लगभग 30,000 पैक्स को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण फरवरी और मार्च माह के दौरान दिया जाएगा, जिससे पैक्स की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे करोड़ों किसानों और ग्रामीण आबादी को फायदा होगा !%%

ट्रेनिंग 28 राज्यों में पीएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में सीएससी द्वारा दी जाने वाली लगभग 300 सेवाओं के बारे में कंप्यूटर पर प्रैक्टिस शामिल होगा। आने वाले महीनों में इन पैक्सों (कृषि ऋण समितियों) पर फॉलो अप कर उसकी सहायता भी की जाएगी। पैक्स का एकत्रीकरण सहकारी समितियों के राज्यीय रजिस्ट्रार (आरसीएस) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की मदद से किया जाएगा।

प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (पैक्स) कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की भूमिका निभाते हुए जल्द ही नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार अपडेट और कानूनी सलाह जैसी कई सेवाओं की की भी जानकारी देगी। वे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और ट्रेनों, बसों और उड़ानों के लिए बुकिंग और साथ ही कृषि-इनपुट के लिए वन-स्टॉप शॉप भी बन जाएंगे।

नाबार्ड के अनुसार, देश भर में लगभग 63,000 पैक्स हैं, जिनमें से 50,000 पैक्स ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में कार्य करने के लिए नामांकन किया है। इनमें से 30,000 सक्रिय रूप से ग्रामीण समुदायों को सीएससी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत वैसे पैक्स जो सीएससी में सेवा दे रहे है उनकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

सहकारिता मंत्रालय इस प्रोग्राम में अपार संभावनाएं देखती है। ऐसी उम्मीद है की पैक्स इस विस्तृत सेवा के साथ न केवल अपने 13 करोड़ किसान सदस्यों को लाभान्वित करेगा बल्कि अतिरिक्त राजस्व भी उत्पन्न कर सकेगा और आत्मनिर्भर आर्थिक संस्थान के रूप में बन जायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के %सहकार से समृद्धि% के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, सरकार ने पैक्स को सीएससी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। इस उद्देश्य के लिए, सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसने पैक्स को ग्रामीण लोगों को 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।

Publication:	Western Times, Pg 2	Edition: Ahmedabad	Print
Published Date:	January 24, 2024		

National Council for Co-operative Training to help 30000 PACS in operating as common service centres

New Delhi, The National Council for Co-operative Training (NCCT) will help 30,000 Primary Agriculture Credit Societies (PACS) in transforming them as Common Service Centres (CSCs) by imparting training to their employees.

The training programme for employees of 30,000 PACS, which have enrolled themselves as Common Service Centres (CSCs), will be conducted during February and March. After the training programme, these PACS will become one-stop shops for many essential services like banking, insurance, Aadhaar updates, and all government-to-citizen e-services.

National Council for Co-operative Training (NCCT) is an Autonomous Society promoted by Ministry of Cooperation, Government of India. Under the dynamic leadership of Union Home Minister and Union Cooperation Minister, the Ministry of Cooperation has taken several measures to strengthen PACS, which are grass root level arms of the short term cooperative credit structure.

Common Service Centres (CSC) are the touchpoints for delivering government-to-citizen e-services directly to citizens without needing to visit government offices.

They establish a physical infrastructure with information and communication technology (ICT) tools. CSC plays a significant role in increasing transparency in service delivery and reducing citizens' burden by bringing essential services closer to their doorsteps. A comprehensive training programme to educate 30,000 PACS that would enable them to offer various services of CSC is all set to kick start from the month of February 2024, said a NCCT official.

"About 80 master trainers associated with NCCT will provide training to about 30,000 PACS spread across 570 districts across India. The training will be imparted during the month of February and March, will enable help enhance income of PACS. This in turn will benefit crores of farmers and rural population," the official said.

The training will be provided at PSC's at 28 states. Training will contain hand on practice on computer systems about 300 services offered by CSCs. In subsequent months there will be follow ups and also hand holding of these PACS. Mobilisation of PACS will be done with the help of State Registrar of Cooperative Societies (RCS) and District Central Cooperative Banks (DCCB's).

Primary Agriculture Credit Societies (PACS) taking on the role of Common Service Centres (CSCs) will soon offer citizens a vast array of services, from banking and insurance to Aadhaar updates and legal advice. They'll even become one-stop shops for agri-inputs like farm equipment, PAN cards, and travel bookings for trains, buses, and flights.

As per NABARD, around 63,000 PACS operate across the country, with 50,000 already enrolled as Common Service Centres (CSCs). Of these, 30,000 are actively offering CSC services, bringing essential services closer to rural communities.

Upcoming training by "Master Trainers" is expected to significantly enhance service delivery and efficiency at PACS-turned-CSCs.

Publication:	Rajasthan Patrika, Pg 17	Edition: Jaipur	Print
Published Date:	January 24, 2024		

एनसीसीटी करेगी मदद

नई दिल्ली. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद 30,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में बदलने में मदद करेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, ये पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेट और सरकार और नागरिकों के बीच सभी आवश्यक सेवाओं सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप शॉप बन जाएंगे।

Publication:	Dainik Jalte Deep, Pg 7	Edition: Jaipur	Print
Published Date:	January 24, 2024		

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद 30000 पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन में मदद करेगी

■ जलतेदीप, नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) 30,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में बदलने में मदद करेगी।

30,000 पैक्स के कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम, फरवरी और मार्च के दौरान आयोजित किया जाएगा ये 30,000 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, ये पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेट और सरकार और नागरिकों के बीच सभी आवश्यक सेवाओं सेवाएँ प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप शॉप बन जाएंगे। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित एक स्वशासी सोसायटी है केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के कुशल नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की मूल स्तर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सरकारी ऑफिसो में जाने की आवश्यकता के बिना नागरिकों को सीधे ई-सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही, वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों के साथ एक भौतिक बुनियादी ढांचा स्थापित करते हैं।

Publication:	Business Remedies, Pg 6	Edition: Jaipur	Print
Published Date:	January 24, 2024		

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद 30000 पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन में मदद करेगी

बिज़नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) 30,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में बदलने में मदद करेगी।

30,000 पैक्स के कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम, फरवरी और मार्च के दौरान आयोजित किया जाएगा ये 30,000 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, ये पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेट और सरकार और नागरिकों के बीच सभी आवश्यक सेवाओं सेवाएँ प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप शॉप बन जाएंगे।

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित एक स्वशासी सोसायटी है। केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के कुशल नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की मूल स्तर हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सरकारी ऑफिसो में जाने की आवश्यकता के बिना नागरिकों को सीधे ई-सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही, वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों के साथ एक भौतिक बुनियादी ढांचा स्थापित करते हैं। सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और अत्यावश्यक सेवाएं लोगों के करीब लाकर उनका बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एनसीसीटी के एक अधिकारी ने कहा कि 30,000 पैक्स को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी 2024 से शुरू होने वाला है, जो उन्हें सीएससी की विभिन्न सेवाओं की सभी जानकारी देने में सक्षम बनाएगा।

एनसीसीटी से जुड़े लगभग 80 मास्टर ट्रेनर पुरे देश के 570 जिलों में फैले लगभग 30,000 पैक्स को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण फरवरी और मार्च माह के दौरान दिया जाएगा, जिससे पैक्स की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे करोड़ों किसानों और ग्रामीण आबादी को फायदा होगा। ट्रेनिंग 28 राज्यों में पीएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में सीएससी द्वारा दी जाने वाली लगभग 300 सेवाओं के बारे में कंप्यूटर पर प्रैक्टिस शामिल होगा। आने वाले महीनों में इन पैक्सों (कृषि ऋण समितियों) पर फॉलो अप कर उसकी सहायता भी की जाएगी। पैक्स का एकत्रीकरण सहकारी समितियों के राज्यीय रजिस्ट्रार (आरसीएस) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की मदद से किया जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (पैक्स) कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की भूमिका निभाते हुए जल्द ही नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार अपडेट और कानूनी सलाह जैसी कई सेवाओं की की भी जानकारी देगी। वे कृषि उपकरण, पैन कार्ड और ट्रेनों, बसों और उड़ानों के लिए बुकिंग और साथ ही कृषि-इनपुट के लिए वन-स्टॉप शॉप भी बन जाएंगे।

Publication:	Dainik Bhor, Pg 3	Edition: Jaipur	Print
Published Date:	January 24, 2024		

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद 30000 पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन में मदद करेगी

नई दिल्ली (एजेन्सी)। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) 30,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में बदलने में मदद करेगी। 30,000 पैक्स के कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम, फरवरी और मार्च के दौरान आयोजित किया जाएगा ये 30,000 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एनसीसीटी के एक अधिकारी ने कहा कि 30,000 पैक्स को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी 2024 से शुरू होने वाला है, जो उन्हें सीएससी की विभिन्न सेवाओं की सभी जानकारी देने में सक्षम बनाएगा। एनसीसीटी से जुड़े लगभग 80 मास्टर ट्रेनर पुरे देश के 570 जिलों में फैले लगभग 30,000 पैक्स को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण फरवरी और मार्च माह के दौरान दिया जाएगा, जिससे पैक्स की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे करोड़ों किसानों और ग्रामीण आबादी को फायदा होगा। ट्रेनिंग 28 राज्यों में पीएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में सीएससी द्वारा दी जाने वाली लगभग 300 सेवाओं के बारे में कंप्यूटर पर प्रैक्टिस शामिल होगा। आने वाले महीनों में इन पैक्सों (कृषि ऋण समितियों) पर फॉलो अप कर उसकी सहायता भी की जाएगी। पैक्स का एकत्रीकरण सहकारी समितियों के राज्यीय रजिस्ट्रार (आरसीएस) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की मदद से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, सरकार ने पैक्स को सीएससी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। इस उद्देश्य के लिए, सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसने पैक्स को ग्रामीण लोगों को 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।

Publication:	Buraeu Sandesh, Pg2	Edition: Jaipur	Print
Published Date:	January 24, 2024		

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद 30000 पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन में मदद करेगी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) 30,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में बदलने में मदद करेगी। 30,000 पैक्स के कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम, फरवरी और मार्च के दौरान आयोजित किया जाएगा ये 30,000 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, ये पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेट और सरकार और नागरिकों के बीच सभी आवश्यक सेवाओं सेवाएँ प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप शॉप बन जाएंगे। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित एक स्वशासी सोसायटी है। केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के कुशल नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की मूल स्तर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सरकारी ऑफिसो में जाने की आवश्यकता के बिना नागरिकों को सीधे ई-सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही, वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों के साथ एक भौतिक बुनियादी ढांचा स्थापित करते हैं। सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और अत्यावश्यक सेवाएं लोगों के करीब लाकर उनका बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीसीटी के एक अधिकारी ने कहा कि 30,000 पैक्स को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी 2024 से शुरू होने वाला है, जो उन्हें सीएससी की विभिन्न सेवाओं की सभी जानकारी देने में सक्षम बनाएगा। एनसीसीटी से जुड़े लगभग 80 मास्टर ट्रेनर पुरे देश के 570 जिलों में फैले लगभग 30,000 पैक्स को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण फरवरी और मार्च माह के दौरान दिया जाएगा, जिससे पैक्स की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे करोड़ों किसानों और ग्रामीण आबादी को फायदा होगा।

ट्रेनिंग 28 राज्यों में पीएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में सीएससी द्वारा दी जाने वाली लगभग 300 सेवाओं के बारे में कंप्यूटर पर प्रैक्टिस शामिल होगा। आने वाले महीनों में इन पैक्सों (कृषि ऋण समितियों) पर फॉलो अप कर उसकी सहायता भी की जाएगी। पैक्स का एकत्रीकरण सहकारी समितियों के राज्यीय रजिस्ट्रार (आरसीएस) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की मदद से किया जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज (पैक्स) कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की भूमिका निभाते हुए जल्द ही नागरिकों को बैंकिंग, बीमा, आधार अपडेट और कानूनी सलाह जैसी कई सेवाओं की की भी जानकारी देगी।

Publication:	Dainik Taj, Pg 3	Edition: Jaipur	Print
Published Date:	January 24, 2024		

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद 30000 पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन में मदद करेगी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) 30,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के सदस्यों को ट्रेनिंग देकर कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में बदलने में मदद करेगी। 30,000 पैक्स के कर्मचारियों के लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम, फरवरी और मार्च के दौरान आयोजित किया जाएगा ये 30,000 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, ये पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेट और सरकार और नागरिकों के बीच सभी आवश्यक सेवाओं सेवाएँ प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप शॉप बन जाएंगे। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा गठित एक स्वशासी सोसायटी है। केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के कुशल नेतृत्व में, सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं, जो अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की मूल स्तर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सरकारी ऑफिसो में जाने की आवश्यकता के बिना नागरिकों को सीधे ई-सेवाएं प्रदान करते हैं। साथ ही, वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों के साथ एक भौतिक बुनियादी ढांचा स्थापित करते हैं।

सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और अत्यावश्यक सेवाएं लोगों के करीब लाकर उनका बोझ कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसीसीटी के एक अधिकारी ने कहा कि 30,000 पैक्स को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक ट्रेनिंग प्रोग्राम फरवरी 2024 से शुरू होने वाला है, जो उन्हें सीएससी की विभिन्न सेवाओं की सभी जानकारी देने में सक्षम बनाएगा। एनसीसीटी से जुड़े लगभग 80 मास्टर ट्रेनर पुरे देश के 580 प्ररोग्रम में फैले लगभग 30,000 पैक्स को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। यह प्रशिक्षण फरवरी और मार्च माह के दौरान दिया जाएगा, जिससे पैक्स की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे करोड़ों किसानों और ग्रामीण आबादी को फायदा होगा। ट्रेनिंग 28 राज्यों में पीएससी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

LOCATIONS OF NCCT INSTITUTES

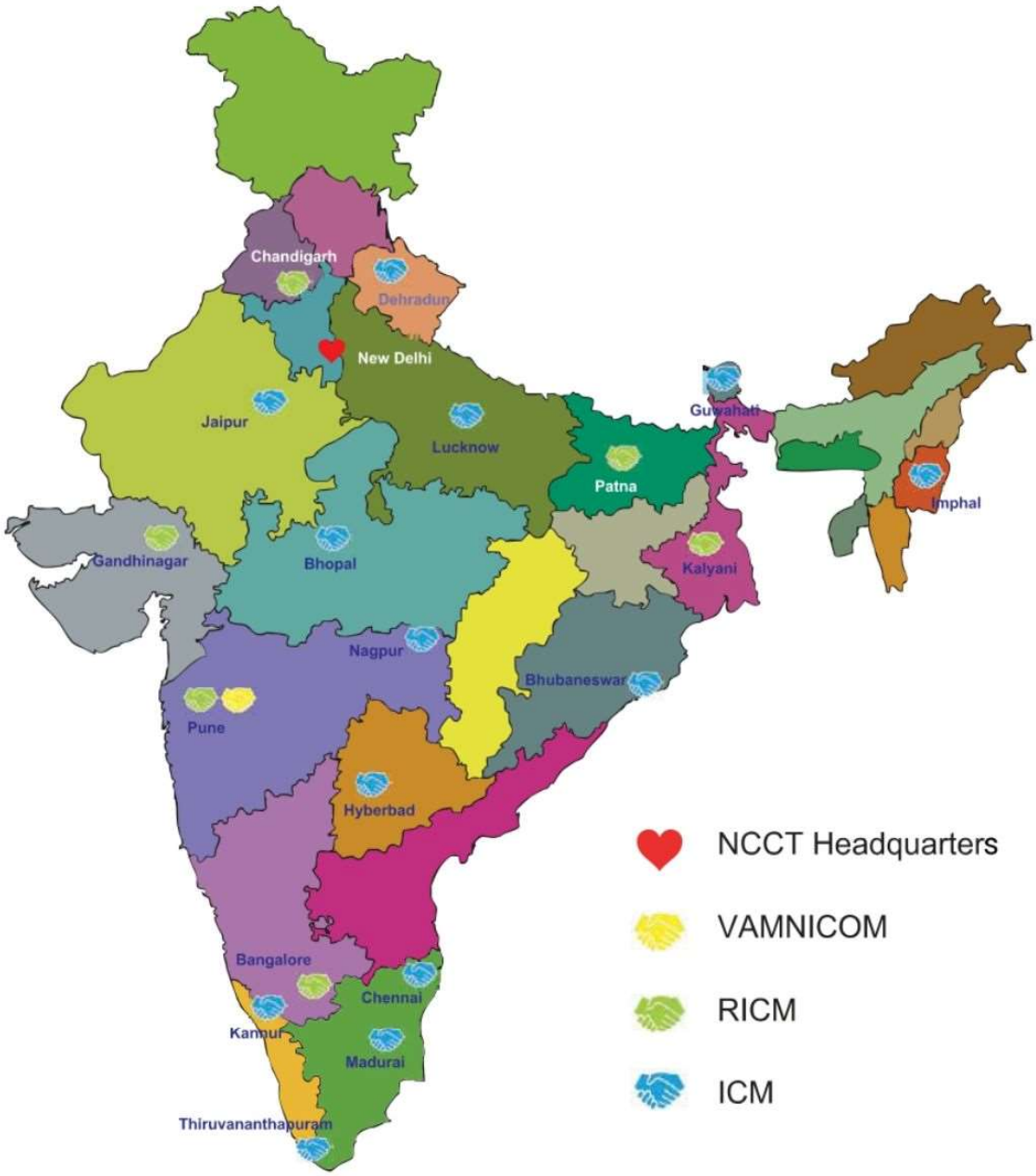

NATIONAL COUNCIL FOR COOPERATIVE TRAINING

(AN AUTONOMOUS SOCIETY PROMOTED BY MINISTRY OF COOPERATION, GOVERNMENT OF INDIA)

3, Siri Institutional Area (3rd Floor), August Kranti Marg, New Delhi-110016

011-41096510 secy-ncct@gov.in www.ncct.ac.in